भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1821
जिसका उत्तर मंगलवार, 02 अगस्त, 2022
11 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है।

अस्थिर बाज़ार की परिस्थितियों में एलआईसी आईपीओ का आरंभ किया जाना

1821 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मुद्रा स्फीति और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अस्थिर बाज़ार की परिस्थितियों के बावजूद मई में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आरंभ करने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा एलआईसी के अंतर्निहित महत्व को कम आंके जाने के क्या कारण हैं, जो आईपीओ के समय मूल्यांकन से काफी अधिक था; और

(ग) सरकार विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसंरचना संबंधी व्यय के वित्तपोषण के लिए एलआईसी का उपयोग किस प्रकार करने की योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) : मई, 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की शुरूआत करने का निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ विविध कारकों जैसे कि मजबूत घरेलू मांग, प्रतिक्रियाशील एंकर बुक, अस्थिरता को कम करने के साथ ही फरवरी, 2022 में यूक्रेन संकट की शुरूआत के समय से बाजार में सुधार को ध्यान में रखकर लिया गया है।

(ख) : एलआईसी के भारतीय एम्बेडेड वेल्यू (आईईवी) को कम नहीं आंका गया है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार, एलआईसी का आईईवी उसके पेशेवर सलाहकारों द्वारा बीमांकक अभ्यास मानकों (Actuarial Practice Standards) के अनुसार 539,686 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एलआईसी का भारतीय एम्बेडेड वेल्यू (आईईवी) 541,492 करोड़ रुपये था।

(ग) : एलआईसी के निवेश बाजार विनियामकों के निवेश विनियमों [भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)] और बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार एवं निवेश संबंधी एलआईसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किए जाते हैं। एलआईसी के निवेश संबंधी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिए जाते हैं।

*****